Impact Factor (QJIF): 8.47 E-ISSN: 2583-1615, P-ISSN: 3049-3498

International Journal of Research in Academic World

Received: 11/November/2025 **IJRAW:** 2026; 5(1):01-03 **Accepted:** 20/December/2025

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 मे समावेशी शिक्षा की अवधारणा एवं वर्तमान युग मे इसकी प्रासंगिकता

[*1]डॉ. अंजली सिंह

[*1]शिक्षक, शिक्षा विभाग, एम.एल.के.पी.जी. कॉलेज, बलरामपुर, उत्तर प्रदेश, भारत।

सारांश

भारत में शिक्षा का स्वरूप समय के साथ निरंतर विकसित होता रहा है। समावेशी शिक्षा (Inclusive Education) एक ऐसी अवधारणा है जिसने सीखने की प्रक्रिया को सभी के लिए समान और उपलब्ध कराने का संकल्प लिया है। भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (NEP 2020) में समावेशी शिक्षा को एक महत्वपूर्ण स्तम्भ के रूप में स्थापित किया गया है। यह नीति विविध पृष्ठभूमि, क्षमता, लिंग, वर्ग तथा आवश्यकताओं वाले छात्रों के लिए एक सहायक, समर्पित और समान शिक्षा प्रणाली का निर्माण करती है। NEP 2020 विविध पृष्ठभूमि को बाधा नहीं, बल्कि शिक्षा की शक्ति मानती है। यह नीति समान अवसर, स्थानीय संदर्भों की मान्यता और आजीवन सीखने के माध्यम से हर शिक्षार्थी को सशक्त बनाने का लक्ष्य रखती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारत की सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषाई, आर्थिक और भौगोलिक विविध पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए एक समावेशी, समानतामूलक और बहुलतावादी शिक्षा व्यवस्था की परिकल्पना करती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारत की शिक्षा व्यवस्था में एक ऐतिहासिक परिवर्तन का दस्तावेज़ है। लगभग 34 वर्षों बाद लागू की गई यह नीति 21वीं सदी की आवश्यकताओं, वैश्विक चुनौतियों और भारत की सामाजिक-सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है। इसका मूल उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण, समावेशी और समानतामूलक शिक्षा के माध्यम से मानव संसाधन का समग्र विकास करना है।

मुख्य शब्द: शिक्षा, समावेशी शिक्षा, आलोचनात्मक चिंतन, शिक्षा नीति, सामाजिक-सांस्कृतिक विविधता आदि।

प्रस्तावना

NEP 2020 का प्रमुख लक्ष्य शिक्षा को केवल डिग्री या परीक्षा-केंद्रित न रखकर ज्ञान, कौशल, मूल्यों और चरित्र निर्माण से जोड़ना है। नीति "सीखने के लिए सीखना" (learning to learn), आलोचनात्मक चिंतन, रचनात्मकता और नवाचार पर बल देती है। इसके अंतर्गत शिक्षा को बोझिल पाठ्यक्रम से मुक्त कर आनंददायक, अनुभवात्मक और जीवनोपयोगी बनाने का प्रयास किया गया है।

समावेशी शिक्षा की अवधारणा

समावेशी शिक्षा का अर्थ है शिक्षा का ऐसा वातावरण जिसमें प्रत्येक छात्र — चाहे उसकी सामाजिक, आर्थिक, मानसिक या शारीरिक क्षमता कोई भी हो — समान अवसर, संसाधन और समर्थन पा सके। इसका उद्देश्य केवल भौतिक रूप से कक्षा में बैठना नहीं है, बल्कि पूर्ण सहभागिता, समर्पण, उपलब्धि और आत्म-सम्मान प्रदान करना है।

समावेशी शिक्षा के मूल तत्व:

- **समान अवसर:** सभी छात्रों के लिए बिना भेदभाव के प्रवेश।
- **सहभागिता:** सभी छात्रों का सीखने में सक्रिय योगदान।
- **समर्थन:** विशेष आवश्यकताओं वाले छात्रों को आवश्यक सहायक सेवाएँ।
- **साक्षरता और कौशल:** हर छात्र को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और कौशल प्रदान करना।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (NEP 2020) भारतीय शिक्षा प्रणाली में एक ऐतिहासिक परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करती है, जिसका अभिप्राय शिक्षा को समावेशी, लचीला, बहु-आयामी तथा कौशल-आधारित बनाना है। यह नीति भारत के विकास के संदर्भ में न केवल वैज्ञानिक और सामाजिक दृष्टिकोण से, बल्कि आर्थिक दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका उद्देश्य देश को एक सशक्त राष्ट्र के रूप में विकसित करना है और वैश्विक ज्ञान समाज में एक अग्रणी स्थान दिलाने का प्रयास करना है। इस शोध में NEP 2020 की संरचना, उद्देश्यों, प्रमुख विशेषताओं, क्रियान्वयन की चुनौतियों और उसके प्रभाव का समग्र और विस्तृत विश्लेषण किया गया है, ताकि नीति के विभिन्न पहलुओं के बारे में गहन समझ प्राप्त किया जा सके।

***Corresponding Author:** डॉ. अंजली सिंह

भारत में शिक्षा नीति का महत्व अत्यंत उच्च है क्योंकि शिक्षा ही किसी भी राष्ट्र की प्रगति का मूल आधार होती है। वर्ष 2020 में पारित NEP, पुरानी नीति 1986 को प्रतिस्थापित करते हुए आधुनिक आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा प्रणाली के पुनर्गठन हेतु लायी गयी। यह नीति 21वीं सदी के गुणवत्तापूर्ण, तकनीकी समर्थ, बहुभाषी और अंतर-अनुशासनात्मक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कृतसंकल्पित है। शिक्षा केवल पाठ्यक्रम तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि यह छात्रों को जीवन में सफल होने के लिए आवश्यक कौशल और ज्ञान प्रदान करने का भी कार्य करती है। विद्यालयी शिक्षा में NEP 2020 ने 5+3+3+4 की नई संरचना प्रस्तुत की है, जो 3 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों को समाहित करती है। प्रारंभिक अवस्था में खेल और गतिविधि-आधारित शिक्षा, मातृभाषा या स्थानीय भाषा में शिक्षण तथा संज्ञानात्मक विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है। इससे बालक की प्राकृतिक जिज्ञासा और सीखने की क्षमता को प्रोत्साहन मिलता है।

उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नीति बहु-विषयक (Multidisciplinary) दृष्टिकोण को अपनाती है। बहु-प्रवेश और बहु-निकास प्रणाली, अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट (ABC), और शोध को प्रोत्साहन देने के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (NRF) की स्थापना जैसे प्रावधान उच्च शिक्षा को लचीला और शोधोन्मुख बनाते हैं। इसके साथ ही व्यावसायिक और कौशल शिक्षा को मुख्यधारा से जोड़ने का प्रयास किया गया है।

NEP 2020 समावेशी शिक्षा पर विशेष बल देती है। सामाजिक, आर्थिक, लैंगिक और क्षेत्रीय रूप से वंचित वर्गों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने हेतु छात्रवृत्ति, डिजिटल पहुँच, विशेष सहायता योजनाएँ और Gender Inclusion Fund जैसे प्रावधान किए गए हैं। दिव्यांग बच्चों के लिए सुलभ अवसंरचना और सहायक तकनीक पर भी जोर दिया गया है।

भाषाई और सांस्कृतिक विविधता NEP 2020 की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। भारतीय भाषाओं, लोकज्ञान, कला और संस्कृति को शिक्षा से जोड़ते हुए नीति राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक आत्मनिर्भरता को सुदृढ़ करती है। साथ ही, वैश्विक दृष्टिकोण अपनाते हुए अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने का लक्ष्य भी रखा गया है।

निष्कर्षतः, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारत को ज्ञान-आधारित समाज और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने की दिशा में एक दूरदर्शी पहल है। यदि इसका प्रभावी क्रियान्वयन किया जाए, तो यह नीति न केवल शिक्षा व्यवस्था में गुणात्मक सुधार लाएगी, बल्कि सामाजिक न्याय, समानता और सतत विकास को भी सशक्त आधार प्रदान करेगी।

इस नीति के उद्देश्यों का विस्तार से अध्ययन करने की आवश्यकता है, ताकि हमें यह समझ में आ सके कि यह किस प्रकार की शिक्षा प्रणाली का निर्माण करना चाहती है और समाज के विभिन्न वर्गों के लिए कैसे व्यापक अवसर सृजित कर सकती है। इसके तहत न केवल गुणवत्ता, लचीलापन और समावेशन पर बल दिया गया है, बल्कि इसके माध्यम से एक ऐसा शैक्षिक वातावरण तैयार करने की कोशिश की गई है जिसमें सभी छात्रों को अपनी पूर्ण क्षमता तक पहुँचने का अवसर मिले। साथ ही, यह नीति शिक्षा के माध्यम से सांस्कृतिक धरोहर और नवाचार को भी बढ़ावा देती है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में समावेशी शिक्षा

NEP 2020 में समावेशी शिक्षा को शिक्षा प्रणाली का मूल भाग बनाया गया है। नीति की मुख्य विशेषताएँ इस प्रकार हैं:

समावेशी नीतिगत दृष्टिकोण

NEP 2020 के अनुसार:

- सभी बच्चों विशेषकर कमजोर और वंचित वर्गों के लिए शिक्षा तक पहुँच सुनिश्चित की जाएगी।
- लिंग, भाषा, क्षमता, सामाजिक पृष्ठभूमि आदि के आधार पर भेदभाव नहीं होगा।
- विशेष शिक्षा जरुरत (SEN), विकलांगता, ग्रामीण व ग्रामीण-शहरी अंतर को ध्यान में रखते हुए नीति लागू की जाएगी।

बहुभाषीयता और सांस्कृतिक विविधता

नीति बच्चों को उनकी मातृभाषा/स्थानीय भाषा में प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने का समर्थन करती है ताकि सीखने की प्रक्रिया सरल और प्रभावी हो।

संसाधन और संरचनात्मक व्यवस्था

- सहायक उपकरण, विशेष शिक्षण सामग्री तथा प्रशिक्षित शिक्षक उपलब्ध कराए जाएंगे।
- स्कूलों में आवश्यक भौतिक सुविधाओं का निर्माण जिससे सभी प्रकार के छात्रों की सहज पहुँच सुनिश्चित हो।
- समर्थन सेवाएँ
- विशेष आवश्यकताओं वाले छात्रों के लिए शिक्षण सहायक, परामर्श सेवाएँ और सहयोगी तकनीक उपलब्ध कराई जाएगी।

वर्तमान युग मे समावेशी शिक्षा की प्रासंगिकता—

वर्तमान समय में समावेशी शिक्षा की प्रासंगिकता अत्यधिक बढ़ गई है। इसके कई कारण हैं:

- **सामाजिक समानता की आवश्यकता:** आज की दुनिया में सामाजिक समानता व समावेशन (Inclusion) पर जोर दिया जाता है। समान शिक्षा सभी को सम्मान और अधिकार प्रदान करती है।
- **विविधता में एकता:** भारत एक बहुभाषी, बहुसांस्कृतिक एवं बहुधार्मिक देश है। यहाँ के बच्चों की शिक्षा में विविधता का सम्मान करते हुए उन्हें समान अवसर प्रदान करना आवश्यक है। समावेशी शिक्षा इस लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता करती है।
- **अर्थव्यवस्था और कौशल विकास:** समावेशी शिक्षा से बच्चों को बेहतर कौशल व दक्षता प्राप्त होती है, जिससे वे आत्मनिर्भर बनते हैं और राष्ट्र के विकास में योगदान दे सकते हैं।
- **तकनीकी और वैश्विक दृष्टिकोण:** डिजिटल लर्निंग, तकनीकी उपकरण और संसाधन हर विद्यार्थी तक पहुँचाना आज आवश्यक है। समावेशी शिक्षा इस दिशा में अग्रसर है, जिससे कोई भी छात्र पीछे न रह सके।

तालिका 1: समावेशी शिक्षा के लाभ

लाभ	विवरण
समान अवसर	सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा
सामाजिक समावेशन	भिन्न क्षमताओं का सम्मान एवं सहयोग
आत्म-विश्वास	बच्चे अपने कौशल को पहचानते हैं
सामूहिक योगदान	समाज और अर्थव्यवस्था के विकास में भूमिका

समावेशी शिक्षा के समक्ष चुनौतियाँ

- सीमित संसाधन और बुनियादी सुविधाओं की कमी।
- शिक्षक प्रशिक्षण में कमी।
- सामाजिक मानसिकता और पूर्वाग्रह।
- ग्रामीण तथा अविकसित क्षेत्रों में शिक्षा तक कठिन पहुँच।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (NEP 2020) स्वतंत्र भारत की तीसरी

शिक्षा नीति है, जो लगभग 34 वर्षों बाद लागू की गई। यह नीति भारतीय शिक्षा व्यवस्था को 21वीं सदी की आवश्यकताओं के अनुरूप ढालने का दावा करती है। यद्यपि इसमें अनेक प्रगतिशील और दूरदर्शी प्रावधान हैं, फिर भी इसके कुछ पक्ष आलोचना के योग्य भी हैं। अतः NEP 2020 की आलोचनात्मक व्याख्या इसके सकारात्मक पक्षों और सीमाओं—दोनों को समझने में सहायक है।

नीति की सकारात्मक उपलब्धियाँ

NEP 2020 का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष इसकी समावेशी और लचीली संरचना है। विद्यालयी शिक्षा में 5+3+3+4 ढाँचा बालकेंद्रित दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करता है। प्रारंभिक शिक्षा में खेल और गतिविधि-आधारित अधिगम, मातृभाषा में शिक्षण तथा रचनात्मकता पर बल बाल विकास के अनुकूल है। उच्च शिक्षा में बहु-विषयक दृष्टिकोण, बहु-प्रवेश एवं बहु-निकास प्रणाली, और अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट जैसे प्रावधान विद्यार्थियों को लचीलापन प्रदान करते हैं। राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (NRF) की परिकल्पना शोध संस्कृति को सुदृढ़ करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है। नीति भारतीय भाषाओं, संस्कृति और ज्ञान परंपरा को महत्व देती है, जिससे शिक्षा का स्थानीयकरण और भारतीयकरण संभव होता है। साथ ही, डिजिटल शिक्षा और प्रौद्योगिकी के उपयोग से शिक्षा की पहुँच बढ़ाने का प्रयास भी सराहनीय है।

समावेशिता पर प्रश्न

यद्यपि NEP 2020 समावेशी शिक्षा की बात करती है, किंतु इसके क्रियान्वयन को लेकर संदेह व्यक्त किए जाते हैं। आर्थिक रूप से कमजोर, ग्रामीण, आदिवासी और हाशिए पर स्थित समुदायों के लिए डिजिटल संसाधनों की उपलब्धता एक बड़ी चुनौती है। डिजिटल डिवाइड के रहते ऑनलाइन शिक्षा सभी के लिए समान अवसर नहीं बन पाती।

इसके अतिरिक्त, नीति में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देने से शिक्षा के व्यावसायीकरण की आशंका भी जताई जाती है, जिससे वंचित वर्गों की पहुँच सीमित हो सकती है।

भाषा नीति पर आलोचना

मातृभाषा या स्थानीय भाषा में प्रारंभिक शिक्षा का सुझाव शैक्षिक दृष्टि से उचित है, किंतु व्यवहारिक स्तर पर इसके कार्यान्वयन में कठिनाइयाँ हैं। प्रशिक्षित शिक्षकों, उपयुक्त पाठ्यसामग्री और बहुभाषी कक्षाओं की कमी इस लक्ष्य की प्राप्ति में बाधा बन सकती है। कुछ आलोचक इसे सामाजिक और राजनीतिक विवादों से भी जोड़ते हैं।

शिक्षक और संसाधन संबंधी चुनौतियाँ

NEP 2020 शिक्षक को शिक्षा प्रणाली का केंद्र मानती है, परंतु शिक्षक प्रशिक्षण, नियुक्ति और कार्यस्थितियों को लेकर ठोस संसाधन और समयबद्ध योजना स्पष्ट नहीं है। नई संरचना और पाठ्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए व्यापक निवेश और प्रशासनिक क्षमता की आवश्यकता है, जो सभी राज्यों में समान रूप से उपलब्ध नहीं है।

संघीय ढाँचे और क्रियान्वयन की समस्या

शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, किंतु NEP 2020 पर यह आलोचना भी की जाती है कि इसमें केंद्रीकरण की प्रवृत्ति दिखाई देती है। विभिन्न राज्यों की भाषाई, सांस्कृतिक और आर्थिक विविधताओं के अनुरूप नीति के लचीले क्रियान्वयन की स्पष्ट रूपरेखा का अभाव एक चुनौती है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एक दूरदर्शी और सुधारोन्मुख दस्तावेज़ है, जिसमें भारतीय शिक्षा को वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाने की क्षमता है। किंतु इसकी सफलता केवल नीति निर्माण से नहीं, बल्कि समानतामूलक, संसाधन-संपन्न और संवेदनशील क्रियान्वयन से जुड़ी है। आलोचनात्मक दृष्टि से यह कहा जा सकता है कि NEP 2020 संभावनाओं से भरपूर है, परंतु इसके उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सामाजिक यथार्थ, आर्थिक असमानताओं और प्रशासनिक चुनौतियों को गंभीरता से संबोधित करना अनिवार्य होगा।

निष्कर्ष

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में समावेशी शिक्षा की अवधारणा भारतीय शिक्षा प्रणाली को अधिक सशक्त, समावेशी और समान अवसर प्रदान करने वाली बनाती है। वर्तमान युग में जहाँ समाज लगातार विविधता व वैश्वीकरण की ओर अग्रसर है, समावेशी शिक्षा शिक्षा के क्षेत्र में समता, सम्मान और स्वीकार्यता की नींव रखती है। समावेशी शिक्षा न केवल छात्रों के व्यक्तिगत विकास में सहायक है, बल्कि सामाजिक, आर्थिक एवं राष्ट्रीय विकास के लिए भी महत्वपूर्ण है।

संदर्भ सूची

1. सिंह, पी. (2024). राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP-2020): सिद्धांत और अवधारणाएँ। काव बुक्स पब्लिकेशन्स।
2. कुमार, ए. (2021). नई शिक्षा नीति (NEP) 2020: भारत 2.0 के लिए एक रोडमैप। डब्ल्यू. बी. जेम्स, सी. कोबानोग्लू, और एम. कैवुसोग्लू (संपादक), ग्लोबल शिक्षा और अनुसंधान में प्रगति (खंड 4, पृष्ठ 1–8)। USF M3 पब्लिशिंग।
3. स्मिता, एस. (2020). राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 – शिक्षक शिक्षा में अवसर और चुनौतियाँ। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ़ मैनेजमेंट, 11(11), 1881–1886।
4. अमीन, जे. ए., वर्मा, एस., और कुमार, एस. (संपादक). (2024). कक्षाओं की पुनर्कल्पना: NEP 2020 के तहत समानता और समावेशन। नित्या पब्लिकेशन्स। ISBN 978-93-5857-921-5।
5. चक्रवर्ती, डी., और गुप्ता, पी. (2024). राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एवं उच्च शिक्षा का स्वरूप। शाश्वत पब्लिकेशन। ISBN 978-81-19908-18-9।
6. मांगलिक, आर. (2024). राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020. एडुगोरिल्ला पब्लिकेशन। ISBN 978-93-71377-539-? (108 पृष्ठ).
7. रथ, पी., कुमार, ए., और सिंह, एम. के. (संपादक). (2023). राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020: LIS शिक्षा और सेवाओं के लिए एक दूरदर्शी दृष्टिकोण। (ISBN 978-93-91734-329). इंडियन बुक्स एंड पीरियोडिकल्स।
8. सेखरी, ए., और अग्रवाल, आर. (2023). नए क्षितिज की ओर: NEP 2020 के कार्यान्वयन में चुनौतियों, विचारों और शिक्षकों की धारणाओं को उजागर करना। इटरेटिव इंटरनेशनल पब्लिशर्स। ISBN 978-93-5747-312-5।
9. वर्मा, एम. के. (संपादक). (2025). राष्ट्रीय शिक्षा नीति और सतत विकास लक्ष्य। रावत बुक्स। ISBN 978-81-316-1471-6।
10. हैंडिक कोंवर, आई. आर., और सरमाह बोरुआ, ए. (संपादक). (2022). राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020: भारतीय शिक्षा प्रणाली में एक बड़ा बदलाव। (ISBN 978-93-92038-426). इंडियन बुक्स एंड पीरियोडिकल्स।
11. सिंघा, आर., और सिंघा, एस. (संपादक). (2020). भारत की नई शिक्षा नीति 2020 का परिप्रेक्ष्य (खंड 1). ISBN 978-81-947458-3-9।